दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, रविवार 19 अप्रैल 2020 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 199

देशभर में संक्रमितों की संख्या 14792, अब तक 488 लोगों की मौत

» कोरोनाग्रस्तों में 30 फीसदी जमाती कोरोना मरीज

नई दिल्ली (आरएनएस)। देशभर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 957 नए मामले सामने आए हैं और 36 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 14,792 हो गई है। जिसमें 12,289 सक्रिय हैं, 2015 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 488 लोगों की मौत हो गई है।

पिछले 24 घंटे में 957 नए मामले और 36 लोगों की मौत- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 957 नए मामले सामने आए हैं और 36 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 14,792 हो गई है। जिसमें 12,289 सक्रिय हैं, 2015 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 488 लोगों की मौत हो गई है।

अब तक देश में ठीक हुए 1992 लोग - स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, देश में कोरोना से मृत्युदर 3.3 फीसदी है। अगर उम्र के हिसाब से विश्लेषण किया जाए तो 14.4 फीसदी मौतें 45 साल तक के लोगों की हुई है। 45-60 फीसदी के उम्र के मरीजों में 10.3 फीसदी, 60 से 75 साल के मरीजों में 33.1 फीसदी और 75 साल से ऊपर के मरीजों में 42.2 फीसदी मृत्युदर रही है।

जमात के लोगों ने बढ़ाई समस्या- शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नियमित प्रेस वार्ता के दौरान करते हुए बताया कि तबलीगी जमात से संबंधित मरीज देश के 23 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में करीब 30 फीसदी कोरोना मरीज सिर्फ तबलीगी जमात से संबंधित हैं। यही नहीं कोविड-19 मरीजों की संख्या के लिहाज से टॉप 10 राज्यों में पांच राज्य ऐसे हैं जहां जमाती मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। उन्होंने बताया कि 14,378 पॉजिटिव केस में 4,291 केस यानी करीब 29.8 फीसदी निजामुद्दीन मरकज से संबंधित पाए गए हैं। इससे 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मरकज से संबंधित मरीज मिले। खासकर तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में मरकज के मरीज ज्यादा पाए गए हैं और ये राज्य कोविड-19 मरीजों की तुलना में टॉप 10 राज्यों में शुमार हो गए। हालांकि अब कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो किसी को भी हैरानी में डाल सकते हैं। अग्रवाल ने कहा कि कुछ राज्यों में अकेले तबलीगी जमात से संबंधित मरीज 91 फीसदी तक पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि असम में 35 में से 32 केस यानी 91 फीसदी, अंडमान में 12 में से 10 यानी 81 फीसदी केस जमात से जुड़े हुए हैं।

दिल्ली में 63 फीसदी जमात के कोरोना मरीज - मंत्रालय के अनुसार टॉप 10 राज्यों में शुमार उपरोक्त पांच राज्यों की बात की जाए तो तमिलनाडु में 84 फीसदी, दिल्ली में 63 फीसदी, तेलंगाना में 79 फीसदी, यूपी में 59 फीसदी और आंध्र प्रदेश में 61 फीसदी केस जमात से संबंधित हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जिसका नाम एक जमाती की वजह से ही कोरोना प्रभावित राज्य में शामिल हो गया है। अग्रवाल ने कहा कि अरुणाचल में जो एक मामला सामने आया, वह तबलीगी जमात से संबंधित है।

जमात की भूमिका पर राजनीति- देश में कोरोना संकट को हवा देने में तबलीगी जमात की भूमिका की चर्चा होते ही कुछ लोग आगबबूला हो उठते हैं और इसे हिंदू-मुस्लिम के बीच खाई बढ़ाने की रणनीति कह देते हैं। पहलवान बबीता फोगाट ने जब तबलीगी जमात की लापरवाही पर चिंता व्यक्त की, तो उन्हें धमकियां मिलने लगीं। हद तो यह हो गई कि सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति राय ने जर्मन न्यूज नेटवर्क डॉचे वेले (ष्ठङ्ख) से बातचीत में यहां तक कह दिया कि भारत सरकार कोरोना संकट की आड़ में मुस्लिमों के नरसंहार की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में तबलीगी जमात के मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? इसका जवाब आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी महत्वपूर्ण आंकड़ों से पाया जा सकता है।

दिल्ली एम्स में गैर-कोरोना रोगियों का भी होगा इलाज- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में 20 अप्रैल से सभी गैर-कोरोना रोगी जिनका यहां इलाज चल रहा था और उन्हें अनुवर्ती (फॉलोअप) उपचार की सलाह दी गई थी, एक अनुवर्ती नियुक्ति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। दी गई तिथि पर, संबंधित विभाग के डॉक्टर इन रोगियों को बुलाएंगे और उन्हें अपेक्षित चिकित्सकीय सलाह देंगे।

20 अप्रैल से टोल प्लाजा पर शुरू हो सकती है टैक्स वसूली

» केंद्र सरकार इस दिशा में तैयार कर रही दिशा निर्देश

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना लॉकडाउन के बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई 20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की वसूली शुरू कर देगा, जिसके लिए सरकार गाइडलाइन बना रही है। हालांकि, सरकार के इस आदेश का परिवहन उद्योग से जुड़े लोगों ने विरोध किया है। सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से टोल टैक्स की वसूली अस्थाई तौर पर रोक दी थी ताकि आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में आसानी हो। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनएचएआई को लिखे पत्र में कहा है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों को राज्य के भीतर और राज्यों में आवागमन के लिए जो छूट दी गयी थी, उसी संबंध में एनएचएआई को गृह मंत्रालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए और टोल टैक्स की वसूली 20 अप्रैल, 2020 से की जानी चाहिए। एनएचएआई के पत्र का जवाब देते हुए, मंत्रालय ने कहा कि एनएचएआई ने 11 और 14 अप्रैल की अपनी चिट्ठियों में टोल टैक्स वसूली शुरू करने का कारण बताते हुए कहा था कि गृह मंत्रालय ने व्यावसायिक एवं निजी प्रतिष्ठानों तथा विनिर्माण गतिविधियों सहित कई कार्यों को 20 अप्रैल से अनुमति दे दी है। पत्र में लिखा है कि एनएचएआई ने कहा है कि टोल टैक्स की वसूली से सरकार को राजस्व मिलता है और इससे एनएचएआई को भी धन लाभ होता है।

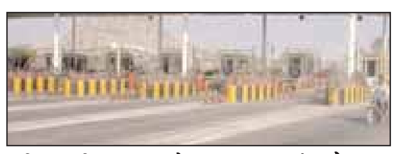

एमएसपी पर सीधे किसानों से दलहन और तिलहन की खरीद का संचालन

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत सरकार, नेफेड और एफसीआई जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से किसानों को बेहतर रिटर्न देने का आश्वासन देती रही है। रबी 2020- 21 सीजन में कई राज्यों में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अधिसूचित वस्तुओं की खरीद शुरू हुई है। लाकडाउन के समय में किसानों को समय पर विपणन सहायता दी जा रही है। कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करके अधिक से अधिक किसानों को सहायता पहुंचाई जा रही है।

रबी सीजन 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत वर्तमान समय में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में किसानों से एमएसपी पर दलहन और तिलहन की खरीद की जा रही है। 16 अप्रैल, 2020 तक नैफेड/एफसीआई द्वारा 1,33,987.65 मीट्रिक टन दाल और 29,264.17 मीट्रिक टन तिलहन की कुल 784.77 करोड़ रुपये की खरीद की गई है, जिसके माध्यम से 1,14,338 किसान लाभान्वित हुए हैं। लाकडाउन अवधि के दौरान पीएसएस योजना के अंतर्गत रबी दलहन और तिलहन की 97,337.35 मीट्रिक टन की खरीद की गई है।

दालों के बफर स्टॉक के लिए नेफेड द्वारा भी मूल्य स्थाईकरण कोष (पीएसएफ) योजना के अंतर्गत किसानों से एमएसपी पर तूर की खरीद की जा रही है। पीएसएस/पीएसएफ खरीफ 2019-20 सीजन के अंतर्गत महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में बड़े पैमाने पर तूर की खरीद की जा रही है। खरीफ विपणन सीजन 2019-20 के दौरान तूर की कुल खरीद 5,32,849 मीट्रिक टन है, जिसमें से 29,328.62 मीट्रिक टन तूर की खरीद लाकडाउन के बाद की गई है। राजस्थान के कोटा डिवीजन में लाकडाउन की घोषणा के बाद दलहन और तिलहन की खरीद बंद कर दी गई। 15.04.2020 से, कोटा डिवीजन के 54 केंद्रों ने कार्य करना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में कई और खरीद केंद्रों को चालू किया जाएगा। राजस्थान के शेष हिस्सों में मई 2020 के पहले सप्ताह से खरीद किया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक खरीद केंद्र में अधिकतम 10 किसानों को प्रति दिन बुलाया जाता है और तदनुसार किसानों को सूचना भेजी जाती है।

20 अप्रैल के बाद छूट की रणनीति का भी तैयार हुआ रोडमैप

» राज्यों को एक और राहत पैकेज जल्द

» जीओएम की बैठक में हुई चर्चा

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के लिए एक और राहत पैकेज की घोषणा करेगी। शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली मंत्रियों के समूह (जीओएम) की मैराथन बैठक में इस पर देर तक माथापच्ची हुई। इसी बैठक में 20 अप्रैल को लॉकडाउन के दौरान मिलने वाली छूट के रोडमैप पर भी चर्चा हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे।

गौरतलब है कि लॉकडाउन की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना से निपटने के लिए 15000 करोड़ का पैकेज घोषित किया था। तब इस रकम का बड़ा हिस्सा कोरोना से ज्यादा संक्रमित राज्यों को दिया गया। इसके बाद कई राज्यों ने लगातार राहत पैकेज की मांग की थी। इनमें वह राज्य ज्यादा थे जिन्हें घोषित पैकेज में हिस्सा नहीं मिला था। सूत्रों ने कहा कि पैकेज देने पर बैठक में सैद्धांतिक सहमति बन गई है। पैकेज कितना बड़ा हो और इसका विभिन्न राज्यों में वितरण किस स्तर पर किया जाए, इस पर जल्द हीफैसला हो जाएगा।

बैठक में 20 अप्रैल के बाद हालात नियंत्रित रहने की स्थिति में मिलने वाली छूट के साथ-साथ इस दौरान स्थिति के जस तस रहने के दौरान किए जाने वाले उपायों पर भी चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने छूट हासिल करने वाले इलाकों की पहचान शुरू कर दी है। ऐसे इलाकों को दी जाने वाली छूट की सूची भी तैयार की जा रही है। रविवार तक इसका रोडमैप तैयार कर लिया जाएगा। इसी दौरान कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित और सामान्य रूप से संक्रमित इलाकों के लिए भी अलग-अलग रोडमैप तैयार किया जा रहा है।जीओएम में राहत दिए जाने पर चर्चा हुई है। राहत दिए जाने के मामले में मंत्रालय बड़ा मददगार साबित हो सकते हैं।

सभी डाक कर्मचारियों को मिलेगी 10 लाख की क्षतिपूर्ति

नईदिल्ली (आरएनएस)। ग्रामीण डाक सेवक सहित डाक कर्मचारी ग्राहकों को मेल डिलीवरी, डाक घर बचत बैंक, डाक जीवन बीमा देने, एईपीएस सुविधा के तहत किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से ग्राहकों के दरवाजे तक धन की निकासी को सरल बनाने के विभिन्न दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, डाक घर स्थानीय राज्य प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के साथ संपर्क कर देश भर में कोविड-19 किट, फूड पैकेट, राशन एवं अनिवार्य दवाओं आदि की प्रदायगी भी कर रहे हें। इस प्रकार, डाक घर विभागीय कर्तव्यों के साथ साथ कोविड-19 के संकट के समय सामाजिक प्रयोजन की भी सेवा कर रहे हैं।

चिकित्सा आपूर्ति के लिए 274 उड़ानें शुरु

नईदिल्ली (आरएनएस)। कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहयोग करने के लिए देश के दूरदराज के हिस्सों में आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति के परिवहन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लाइफलाइन उड़ान उड़ानें संचालित की जा रही हैं। लाइफलाइन उड़ान के अंतर्गत एयर इंडिया, अलायंस एयर, आईएएफ और निजी विमान कंपनियों द्वारा 274 उड़ानें संचालित की गई हैं। इन उड़ानों में से 175 एयर इंडिया और अलायंस एयर द्वारा संचालित की गई हैं। इनमें अब तक ले जाया गया कार्गो लगभग 463.15 टन रहा है। लाइफलाइन उड़ान की अब तक की हवाई दूरी 2,73,275 किमी से अधिक रही है।

पवन हंस लिमिटेड समेत हेलीकाप्टर सेवाएं जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, द्वीप और पूर्वोत्तर क्षेत्र में महत्वपूर्ण चिकित्सा कार्गो और रोगियों के परिवहन का काम कर रही हैं। घरेलू लाइफलाइन उड़ान की उड़ानें हब और स्पोक मॉडल में काम करती हैं। कार्गो केंद्र दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलोर और गुवाहाटी में स्थापित किए गए हैं। लाइफलाइन उड़ान की उड़ानें इन केंद्रों को डिब्रूगढ़, अगरतला, ऐजवाल, दीमापुर, इम्फाल, जोरहाट, लेंगपुई, मैसूरू, नागपुर, कोयंबटूर, त्रिवेंद्रम, भुवनेश्वर, रायपुर, रांची, श्रीनगर, पोर्ट ब्लेयर, पटना, कोचीन, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, जम्मू, कारगिल, लद्दाख, चंडीगढ़, गोवा, भोपाल और पुणे के हवाई अड्डों (स्पोक्स) से जोड़ती हैं।

पूर्व डायरेक्टर सुरेन्द्र मोहन ने बहन के साथ पीएम केयर्स में दिया 1 करोड़ का दान

नईदिल्ली (आरएनएस)। कोरोनावायरस और इससे बढ़ती समस्याओं के खिलाफ सरकार और आम लोग मिलकर जंग लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद इस जंग में साथ देने के लिए कई लोग सामने आ रहे हैं। ऐसे में आम लोग हो या खास सभी अपने-अपने व्यक्तिगत हैसियत के हिसाब से पीएम केयर्स में दान कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो संकट की इस घड़ी में अपना सबकुछ देश पर न्योछावर कर देते हैं। ऐसे ही हैं सुरेंद्र मोहन, जिन्होंने अपने भविष्य को नजरअंदाज करते हुए जीवनभर की कमाई पीएम केयर्स फंड में दान कर दी। इस नेक काम में उनकी बहन अदिति ने भी साथ दिया। दोनों सीनियर सिटीजन हैं। गौरतलब है कि सुरेंद्र मोहन रक्षा विभाग से डायरेक्टर पद से 2019 में सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने रिटायरमेंट से मिले हर फायदे को प्रधानमंत्री केयर्स फंड में दान कर दिया है। इसके साथ ही उनकी बहन अदिति ने भी अपने जीवनभर की कमाई, जो उन्होंने फिक्स डिपॉजिट में रखे थे, उसे भी प्रधानमंत्री केयर फंड में दान दे दिया।

कोरोना मरीजों के लिए सीएफटीआरआई ने बनाए उच्च प्रोटीन बिस्किट

» जल्द उबरने में मिलेगी मदद

नईदिल्ली, 18 अप्रैल (आरएनएस)। देश के विभिन्न अनुसंधान संस्थान कोविड-19 खिलाफ मुहिम में अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक ऐंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सीएसआईआर) की मैसूर स्थित प्रयोगशाला सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएफटीआरआई) ने कोविड-19 के मरीजों को ध्यान में रखकर उच्च प्रोटीन युक्त बिस्किट बनाए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रोटीन की प्रचुर मात्रा से युक्त ये पौष्टिक बिस्किट मरीजों को कोविड-19 से जल्दी उबरने में मदद कर सकते हैं।

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (एम्स), नई दिल्ली में उपचार करा रहे कोविड-19 के मरीजों लिए ये बिस्किट सीएफटीआरई की ओर से भेजे गए हैं। उच्च प्रोटीन युक्त 500 किलोग्राम बिस्किट और 500 किलोग्राम रस्क एम्स के आहार विज्ञान विभाग को उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इसे कोविड-19 से प्रभावित मरीजों के आहार में शामिल किया जा सके। सीएफटीआरआई की ओर से ये बिस्किट एम्स के अधिकारियों के आग्रह पर उपलब्ध कराए गए हैं।

इस बिस्किट को बनाने के लिए गेहूँ का आटा, मैदा, चीनी, हाइड्रोजेनेटेड फैट, सोया आटा, व्हे प्रोटीन (ड्ढद्गद्द4 क्क्रश्व्हद्गद्वठ्ठ), सोया प्रोटीन, मिल्क सॉलिड्स, ग्लूकोज, नमक और फ्लेवर्स का उपयोग किया गया है। इस बिस्किट के 100 ग्राम के पैकेट से 400 किलो कैलोरी के ऊर्जा मिल सकती है। इसके पोषण मूल्य में कार्बोहाइड्रेट (63.2 ग्राम), प्रोटीन (14 ग्राम), वसा (17.1 ग्राम) और खनिज (1.2 ग्राम) शामिल है।

कोविड-19 के मरीजों के लिए विशेष रूप से बनाए गए इस बिस्किट में प्रोटीन की मात्रा 14 प्रतिशत है, जो 8-9 प्रतिशत प्रोटीन वाले आम बिस्किट की तुलना में काफी अधिक है। सीएसआईआर-सीएफटीआरआई के निदेशक के.एस.एम.एस राघवराव ने बताया कि ये पौष्टिक बिस्किट मरीजों को जल्द स्वस्थ होने के लिए आवश्यक प्रोटीन उपलब्ध करा सकते हैं।

एम्स की मुख्य डाइटीशियन डॉ परमीत कौर कहती हैं- यहाँ यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि प्रोटीन युक्त इस बिस्किट की रेसिपी सीएसआईआर-सीएफटीआरआई, मैसूर के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई है। अस्पताल में अन्य लोगों के साथ इलाज करा रहे कोविड-19 रोगियों को बिस्किट उनके नियमित आहार के हिस्से के रूप में दिए जाएंगे।

महत्वपूर्ण एवं खास

अमेरिका में 24 घंटों में 3800 की मौत

वाशिंगटन। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस 'कोविड-19' के 31,905 नये मामले सामने आये हैं और इस दौरान 3857 लोगों की मौत हुई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में मृतकों की संख्या बढ़कर 36,997 हो गयी है तथा कुल 7,01475 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 11 मार्च को कोविड-19 को महामारी घोषित कर चुका है। विश्वभर के आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस से 22 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं जबकि इससे मरने वालों की संख्या 154000 के पार हो गई है। कोविड-19 से दुनियाभर में 22 लाख से अधिक संक्रमणों के साथ शुक्रवार को इससे होने वाली मौतों की संख्या 150,000 का आंकड़ा पार कर गई है। वहीं इस महामारी से संयुक्त रूप से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अपने सामूहिक प्रयासों को तेज कर दिया है।

ब्रिटेन में कोरोना से 7,500 से ज्यादा मौतों की आशंका

लंदन । यूरोप में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अभी यहां आंकड़े और भयावह हो सकते हैं। दरअसल अभी तक यह चर्चा चल रही थी कि केयर होम्स में हुई मौतों को अभी तक कुल संख्या में जोड़ा नहीं गया है। अब ब्रिटेन की एक फर्म ने दावा किया है कि देश में अब तक 7500 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना वायरस के चलते केयर होम्स में हो चुकी हैं। देश के हेल्थ सेक्रटरी मैट हैनकॉक ने बताया है कि अब इसकी गिनती शुरू कर दी गई है। देश में अब तक कुल 14,576 लोगों की मौत कोरोना के चलते हो चुकी है।

कोरोना से 1,000 से अधिक लोगों की मौत

जोहानिसबर्ग। अफ्रीका में कोरोना वायरस महामारी के कारण 1,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अफ्रीका के रोग नियंत्रण एवं बचाव केंद्र ने यह जानकारी दी है जबकि नाइजीरिया ने बताया कि राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ की भी वायरस के चलते मौत हो गई। अफ्रीकी महाद्वीप के 54 में से कुल 52 देशों में कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं जहां संक्रमितों की कुल संख्या 19,800 है। नाइजीरिया सरकार ने बताया कि राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी के चीफ ऑफ स्टाफ अब्बा कयारी की शुक्रवार को कोविड-19 से मौत हो गई। बयान में कहा गया, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। कयारी का मामला अफ्रीका के हाई प्रोफाइल मामलों में से एक है। इससे पहले बुर्कीना फासो में कई सरकारी मंत्री और एक अमेरिकी राजदूत संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने शुक्रवार को गौर किया कि अफ्रीका में पिछले एक हफ्ते में 51 प्रतिशत मामले बढ़े हैं और मौत में 60 प्रतिशत वृद्धि हुई है। लेकिन डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने आगाह किया है कि जांच की कमी की वजह से, यह संभव है कि वास्तविक संख्या सामने आए मामलों से अधिक हो। अफ्रीका सीडीसी ने कहा कि अगले हफ्ते से 10 लाख से ज्यादा जांच किट दिए जाएंगे।

किसानों की मदद के लिए ट्रंप देंगे 19 अरब डॉलर

वाशिंगटन,18 अप्रैल । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित किसानों और रिंचरों की मदद के लिए 19 अरब डॉलर के राहत कार्यक्रम की घोषणा की है। अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) के अनुसार कोरोनोवायरस खाद्य सहायता कार्यक्रम कृषि उत्पादकों के लिए वास्तविक नुकसान के आधार पर सीधे 16 अरब डॉलर की मदद देगा, जहां इस महामारी के कारण कीमतें और बाजार की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यूएसडीए क्षेत्रीय और स्थानीय वितरकों के साथ साझेदारी भी करेगा, जिनका काम कई रेस्तरां, होटल और अन्य खाद्य सेवा संस्थाओं के बंद होने से काफी प्रभावित हुआ है। इन वितरकों को ताजा उत्पाद, डेयरी और मीट उत्पाद खरीदने के लिए 3 बिलियन डॉलर की मदद दी जाएगी। व्हाइट हाउस की शुक्रवार को हुई प्रेस ब्रीफिंग में ट्रम्प ने कहा, इससे हमारे किसानों और हमारे रिंचर्स को मदद मिलेगी और वह यह पैसा प्राप्त करने के योग्य हैं।